



# INDEPENDENT INDIA @ 75: SELF RELIANCE WITH INTEGRITY



स्वतंत्र भारत @ 75 :  
सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

VIGILANCE AWARENESS WEEK  
26<sup>th</sup> October – 01<sup>st</sup> November 2021

सतर्कता बुलेटिन  
VIGILANCE BULLETIN



## Sardar Vallabhbhai Patel

(31<sup>st</sup> October 1875 – 15<sup>th</sup> December 1950)

Vigilance Awareness Week is observed every year as a mark of respect to Sardar Vallabhbhai Patel.





## अस्वीकरण

यह पुस्तिका केवल सांकेतिक है तथा किसी भी रूप में यह सर्वांगीण नहीं है और न ही विषयक नियमों, प्रक्रियाओं तथा वर्तमान अनुदेशों/दिशानिर्देशों का प्रतिस्थापन है और न ही इसमें दी गई विषयवस्तु किसी भी रूप में सीवीसी/रेलवे/राइट्स संहिता के नियम का अधिक्रमण करती है। अतः इसे संबंधित नीति के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए ताकि संगत मामले को वास्तविक रूप में समझा जा सके। यह पुस्तिका किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां अनिवार्यता संबंधित विषय के मूल आदेशों का संदर्भ लेना चाहिए। इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य केवल संदर्भ मात्र है।

## DISCLAIMER

The handbook is only indicative and is by no means exhaustive, nor is it intended to be a substitute for rules, procedures and existing instructions / guidelines on the subject. The contents herein do not in any way supersede the rules contained in any of the CVC / RAILWAYS / RITES codes and should be read with relevant policy circulars for proper appreciation of the issues involved. This handbook also should not be produced in any court of law and whenever necessary, reference should always be made to the original orders on the subject. The primary purpose of the handbook is for reference only.



## भ्रष्टाचार के खिलाफ भागीदारी – ईमानदारी की शपथ

### नागरिकों के लिए

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है.

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए.

अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा;

## PARTICIPATE AGAINST CORRUPTION – INTEGRITY PLEDGE

### For individual citizens

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behavior;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.



## संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है.

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हमें अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करनी होगी.

मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा.

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि:-

हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;

हम न तो रिश्वत लेंगे और न ही रिश्वत देंगे;

हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;

हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;

हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे;

हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;

हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे;

हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे;

## Integrity Pledge for Organizations

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice, and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitise our employees of laws, regulations etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.



राष्ट्रपति  
भारत गणतंत्र  
**PRESIDENT**  
**REPUBLIC OF INDIA**

### MESSAGE

I am happy to know that the Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week on the theme "Independent India @ 75: Self Reliance with integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" from 26th October to 1st November 2021.

As a nation, we have had a long and well-established tradition of integrity and ethics. It is our responsibility as citizens to re-affirm these ideals as we strive towards national development and self-reliance. It is the duty of all the citizens to be vigilant and combat corruption in every sphere of life.

I am happy to see that the Central Vigilance Commission is taking the necessary steps to bring the citizens together to strengthen our commitment towards progress and self-reliance while remaining rooted in our ideals.

I extend my greetings to all those associated with the organization of Vigilance Awareness Week at Central Vigilance Commission and wish the campaign every success.

*Ram Nath Kovind*

(Ram Nath Kovind)

New Delhi  
October 05, 2021





भारत के उपराष्ट्रपति  
VICE-PRESIDENT OF INDIA

**MESSAGE**

I am pleased to learn that the Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week this year from 26<sup>th</sup> October to 1<sup>st</sup> November, 2021.

The theme of this year's Vigilance Awareness week is **"Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"** which is in consonance with the journey that our country has had since its independence. A Self-reliant India is a dream for all her citizens and such a dream can only be fulfilled with the participation of all. I have faith that everyone would adopt integrity and ethics in their daily life as we move in our journey towards self-reliance.

I hope to see all citizens and stake holders collectively participate in large numbers in the fight against corruption. We need to come together to reiterate the ideals of integrity, transparency and accountability and strive towards embracing the values that have guided us in our journey so far.

On this occasion, I commend the Central Vigilance Commission for their efforts in combating corruption and convey my best wishes for the success of Vigilance Awareness Week, 2021.

  
(M. Venkaiah Naidu)





सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री  
Prime Minister

## संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 01 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकारी प्रसन्नता हुई।

भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जन भागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल भी करता है।

भारत का जन-सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरुकता सप्ताह के विषय के रूप में 'स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' का चयन प्रशंसनीय है।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ देश गत 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र और निरंतर प्रयासों से देश में एक विश्वास कायम हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है।

आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिन्दगी को आसान बना रही हैं। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया गया है, उसने सामान्यजन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है।

आज देश में जो सरकार है, वह देश के नागरिकों पर भरोसा करती है। पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन-जन में यह भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता।

आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। अमृत काल में हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है- राष्ट्र प्रथम। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग का यह आयोजन, एक बेहतर भविष्य के लिए जीवन में, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस पहल और भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।



(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली  
कार्तिक 03, शक संवत् 1943  
25 अक्टूबर, 2021





**केन्द्रीय सतर्कता आयोग**  
**CENTRAL VIGILANCE COMMISSION**

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023  
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,  
Block A, INA, New Delhi-10023  
019/VGL/029

सं./No..... 11.10.2021

दिनांक / Dated.....

**MESSAGE**

**Vigilance Awareness Week (26<sup>th</sup> October to 1<sup>st</sup> November, 2021)**

It is a matter of pleasure that during the current year the Commission has issued the guidelines for observing Vigilance Awareness Week from 26<sup>th</sup> October, 2021 to 1<sup>st</sup> November, 2021. The theme for the current year's Vigilance Awareness Week is as under:

**“स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”**

**“Independent India @ 75: Self-Reliance with Integrity”**

Self-reliance and integrity are the two ideals which need focus as they are important for achieving all-round progress and development of the country. During the Vigilance Awareness Week there is an opportunity for all to re-affirm ourselves towards our collective duty and responsibility to ensure transparency and integrity in the systems and procedures.

This year a special initiative has been taken to create awareness for the complaint mechanism available under the Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. During the current year, all the organizations have also been requested to focus on improvements in internal processes and other house-keeping activities.

The Commission appeals to all the citizens of the country to come forward, during the 75<sup>th</sup> year of Independence, and support the drive to achieve self-reliance with integrity.

**(SURESH N. PATEL)**

**Central Vigilance Commissioner**





**राहुल मित्तल**

प्रिय साथियों,

आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।

स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म-दिवस अर्थात 31 अक्टूबर जिस सप्ताह में आता है, उसे प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक मनाए जा रहे इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए **“स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”** विषय का चयन किया है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नए आत्मनिर्भर भारत (Self Reliant India) का एक विजन सामने रखा गया है। इस वर्ष का विषय सभी को, विशेषतः युवा पीढ़ी को एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है जिसमें सच्चाई और ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और नए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। देश के पास जनसांख्यिकी लाभ उठाने का अवसर है जिससे आर्थिक विकास करते हुए आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है।

राइट्स में निवारक सतर्कता के द्वारा कार्यों में स्पष्टता लाने के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि व्यक्तिगत स्वविवेक से बचा जा सके और साथ ही नियमों का अक्षरशः पालन हो। अनियमितता और चूक की जांच के लिए सतर्कता विभाग द्वारा कार्यस्थलों पर गहन जांच की जाती है। प्रणालीगत सुधार के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाते हैं ताकि अन्य कार्यस्थलों पर गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। यदि युवाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा सभी के लिए समान अवसर जैसे गुण विकसित किए जाएं तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब भ्रष्टाचार मुक्त नए भारत के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में राइट्स सतर्कता टीम सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है जिसमें भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, व्याख्यान, उधमियों के साथ बैठक, आउटरीच गतिविधियों जैसे ग्राम सभा, सेमिनार तथा इस बुलेटिन का प्रकाशन शामिल है। आप सभी इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें।

आइए, इस अवसर पर हम भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सत्यनिष्ठा को अपनी जीवनशैली के रूप में अपनाने का संकल्प लें।

*21.11.2021*

**(राहुल मित्तल)**  
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**





**Rahul Mithal**

Dear Colleagues

My greetings to all of you.

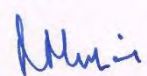
The week in which 31<sup>st</sup> October, the birthday of late Sardar Vallabhbhai Patel falls is observed as Vigilance Awareness Week every year. Central Vigilance Commission (CVC) has chosen **“Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity”** as the theme for this year’s Vigilance Awareness Week, being observed from 26<sup>th</sup> October to 1<sup>st</sup> November 2021.

A vision of New Atmanirbhar Bharat (Self Reliant India) has been unfolded by our Hon’ble Prime Minister. The theme of this year emphasizes the importance of inspiring everyone, especially the young generation to lead a life that combines righteousness and honesty, eradicate corruption, and achieve the goal of a New Atmanirbhar Bharat. There is a great opportunity for the country to reap a demographic dividend powering India’s economic growth on the path to self-reliance. The initiative taken by the Government for the vision of a Self-Reliant India is showing results in all sectors.

As a part of Preventive Vigilance in RITES, training is being imparted at all levels to bring clarity, so as to avoid personal discretion, underlining the importance that the rules are followed in their letter and spirit. Intensive examination is carried out by Vigilance Cell at sites, to check for irregularities and lapses. Office Memorandums for systemic improvement are issued to provide learning and avoid repetition of mistakes at other sites. The day to achieve the target of building corruption free New India is not far, if qualities like Honesty, Transparency, Fairness and Equitable opportunities for all are inculcated in the young.

I am glad to note that RITES Vigilance Team, under the guidance of Chief Vigilance Officer, is organizing a number of programs including Elocution Competition, Essay Writing Competition, Lectures, Vendors’ Meet, Outreach activities like Gram Sabha, Seminars and release of this Vigilance Bulletin, during the Vigilance Awareness Week-2021. I wish that all employees take an active participation in these activities.

On this occasion, let us pledge to practice and make integrity a way of life, to propel our nation towards the vision of a corruption free and Self-Reliant India.



**(Rahul Mithal)**  
**Chairman & Managing Director**





अशोक कुमार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक मनाया जा रहा है, जिसका विषय है **“स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”**। भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम हम सभी जानते हैं। गहरी जड़ें जमाए हुए भ्रष्टाचार उन मुख्य कारणों में से एक है जो हमारे राष्ट्र की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। सत्यनिष्ठा को जीवन शैली के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया जा सकता है।

एक व्यक्ति के रूप में, आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वयं को स्वीकार करना, आंतरिक आत्मविश्वास का निर्माण करना, स्वयं निर्णय लेना, अपने मूल्यों का होना है। इस नैतिक कार्य प्रणाली की सामूहिक चेतना हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाएगी।

हाल ही में आई महामारी से हम आत्मनिर्भरता का महत्व जान गए हैं। इस वर्ष हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए मुख्य विषय के रूप में **“स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”** के चयन के पीछे सीवीसी का मुख्य विचार युवा पीढ़ी को एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है जिसमें न्याय परायणता और ईमानदारी से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार के सतत् प्रयासों के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हालाँकि, अभी भी हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया जाना है। मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है कि उनमें उच्चतम स्तर की ईमानदारी को अपनाकर किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता और ऊर्जा है, चाहे वह लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो। हमारी भूमिका यह होनी चाहिए कि हम उनका किशोर अवस्था में मार्गदर्शन करें ताकि वे तथाकथित सफल और आरामदायक जीवन जीने के लिए अनैतिक मार्ग का अनुकरण न करें।

इसे ध्यान में रखते हुए, राइट्स विजिलेंस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर **“स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”** मुख्य विषय पर राइट्स कर्मचारियों के लिए व्याख्यान, भाषण प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता सहित आउटरीच गतिविधियों जैसे उधमियों के साथ बैठक, ग्राम सभा का आयोजन कर रहा है तथा इस बुलेटिन का प्रकाशन कर रहा है।

हमने इस सतर्कता बुलेटिन में निवारक जाँचों के अपने अनुभव के आधार पर केस अध्ययन, कुछ लेख और कविताएं शामिल की हैं। मुझे विश्वास है कि यह बुलेटिन राइट्स के युवा पेशेवरों को हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सत्यनिष्ठा को अपनी जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्ध एवं अनुपालन हेतु प्रेरित करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे संगठन के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं को ईमानदारी के उच्चतम मानकों के एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे ताकि युवा पेशेवर उनसे प्रेरित हो सकें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की गतिविधियों के बारे में आपकी सच्ची प्रतिक्रियाओं का स्वागत है ताकि हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 को बेहतर बना पाएं।

*Ashok Kumar*

(अशोक कुमार)  
मुख्य सतर्कता अधिकारी





**Ashok Kumar**

Vigilance Awareness Week is being observed this year from 26<sup>th</sup> October to 1<sup>st</sup> November 2021 with the theme of **“Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity”** as per the directives of Central Vigilance Commission. The evil effects of corruption are well known to all of us. The deep-rooted corruption is one of the main causes which are adversely affecting the progress of our nation. The dream of Self-Reliant India can be achieved by adopting Integrity as a way of life.

For individual, self reliance is to accept your self, build inner confidence, making own decisions, having own values. This collective consciousness with ethical conduct will make our nation self Reliant.

The recent pandemic has shown us the importance of Self Reliance. This year we are celebrating the 75 year of Independence. The idea of CVC behind choosing **“Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity”** as main theme for this year’s Vigilance Awareness Week is to inspire the young generation to lead a life that combines righteousness and honesty to make the Self-Reliant India.

Sustained efforts of Govt. of India to curb corruption are giving good results. However, still it’s a long way to go to make our nation corruption free. I have utmost faith in youth of our nation who has potential and energy to achieve any target however tough it may be by adopting highest standards of integrity. Our role is to guide them in the tender age not to fall prey to unethical means to have so called successful and comfortable life.

Keeping this in mind, RITES Vigilance is organizing various activities including Lecture, Elocution competition and Essay writing competition for RITES employees on the main theme of **“Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity”** Outreach activities like Vendors meet, Gram Sabha and publishing of this bulletin to commemorate Vigilance Awareness Week.

We have included case studies based on our experience of preventive checks, some articles and poems in this vigilance bulletin. I hope that this bulletin will inspire young professionals of RITES to pledge and practice to make integrity a way of their life to make our country Self Reliant. I expect senior officers of our organization to set themselves as an example for highest standards of probity so that the young professionals can look up to them and get inspired. A genuine feedback about the activities of Vigilance Awareness Week from one and all will be highly appreciated for better performance during Vigilance awareness Week of 2021.



**(Ashok Kumar)**  
**Chief Vigilance Officer**





**वी. गोपी सुरेश कुमार**

मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार राइट्स का सतर्कता विंग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार **"स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"** विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है।

जैसा कि संथानम समिति की रिपोर्ट, 1964 में कहा गया है, "भ्रष्टाचार को तब तक समाप्त या काफी कम नहीं किया जा सकता है जब तक कि निवारक उपायों की योजना नहीं बनाई जाती और उन्हें निरंतर और प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जाता है। निवारक कार्रवाई में प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षाप्रद उपाय शामिल होने चाहिए।" रोकथाम इलाज से बेहतर है। मेरे विचार से निवारक सतर्कता दंडात्मक सतर्कता से अधिक महत्वपूर्ण है। निवारक सतर्कता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राइट्स ने दिन-प्रतिदिन की विभिन्न गतिविधियों से निपटने के लिए नियम, प्रक्रियाएं, नियमावली और शक्तियों की अनुसूची निर्धारित की है। राइट्स ने जुलाई 2019 में मानक निविदा दस्तावेज भी जारी किए हैं और सुधार पर्व के माध्यम से इन दस्तावेजों को लगातार अद्यतन करने का कार्य भी नियमित रूप से किया जाता है। ये सभी दस्तावेज मिलकर स्वविवेक और मनमानी को कम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का उन्मूलन होता है। सीवीसी या राइट्स विजिलेंस द्वारा जांच के दौरान जहां कहीं भी कमियां पाई जाती हैं, वहां स्वविवेक को कम करने के लिए हमें नियमों में निरंतर सुधार और सरलीकरण और तकनीकी हस्तक्षेप के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में हम ई-प्रोक्योरमेंट और ई-ऑफिस को लागू कर आगे बढ़ें।

भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सीवीसी ने इस वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आम जनता को आगे आने के लिए प्रेरित / जागरूक करने के लिए पीआईडीपीआई (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा) के व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। सत्यनिष्ठा के उच्च मानक को अपनाकर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

मैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी और उनकी टीम को सप्ताह के दौरान गतिविधियां संचालित करने और इस बुलेटिन को प्रकाशित करने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मैं सभी कर्मचारियों से पूरे वर्ष सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के उच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आग्रह करता हूं।

*वी. जी. सुरेश कुमार*

**(वी. गोपी सुरेश कुमार)  
निदेशक परियोजना**





**V. Gopi Suresh Kumar**

I am happy that Vigilance Wing of RITES is organizing vigilance awareness week from 26<sup>th</sup> October to 1<sup>st</sup> November 2021 with theme of “**Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity**” as per the directives of Central Vigilance Commission.

As stated in Santhanam Committee Report,1964 “Corruption cannot be eliminated or even significantly reduced unless preventive measures are planned and implemented in a sustained and effective manner. Preventive action must include administrative, legal, social, economic and educative measures”. Prevention is better than cure. In my view, preventive vigilance is more important than punitive vigilance. To make preventive vigilance more effective, RITES has laid down rules, procedures, manuals and Schedule of Powers to deal with various day to day activities. RITES has also issued standard Tender documents in July 2019 and continuous updating of these documents through correction slips is also undertaken regularly. All these documents, together, reduce the discretion and arbitrariness which results in eradication of corruption. We should strive for continuous improvement and simplification of rules and technological intervention to reduce the discretion wherever gaps are found during checks by CVC or RITES Vigilance. In this direction, we have moved forward by implementing E-Procurement and E-office.

Steps are being taken towards the eradication of corruption. CVC this year has given emphasis on wide publicity of PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informer) to motivate/ aware the common public to come forward to expose the corruption in Central Government offices. By adopting the high standard of Integrity, the goal of self reliance can be achieved.

I congratulate CVO and his team for their efforts for undertaking the activities during the week and for bringing out this bulletin. I will urge upon all the employees to continue their commitment towards higher standards of probity in public life, throughout the year.



**(V. Gopi Suresh Kumar)**  
**Director Projects**





**अनिल विज**

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सरकार तथा नागरिकों के बीच विश्वास स्थापित करने का एक अनिवार्य घटक है। भारत में, प्रत्येक वर्ष, सभी लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों और क्रियाकलापों के निर्वहन में उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के पालन के लिए की गई प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।

स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले समारोहों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय **"स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"** चुना गया है।

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा निश्चित रूप से एक बार का मामला नहीं है, बल्कि एक लोक सेवक के जीवन और आचरण में हर समय और परिस्थितियों 24 x 7 प्रकट होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा का अर्थ भ्रष्टाचार और रिश्वत आदि के उन्मूलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे भी बहुत कुछ है और निश्चित रूप से यह अर्थ है कि सही तरीके से सही काम किया जाए। इसलिए जहां नकारात्मक व्यवहार का उन्मूलन महत्वपूर्ण है, वहीं सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ता एवं बल प्रदान करना उतना ही महत्वपूर्ण है।

भारत, 75 वर्ष की आयु में, अभी भी एक युवा राष्ट्र है और निर्माण की प्रक्रिया में है। जनसांख्यिकी की दृष्टि से भी, भारत एक युवा देश है, जिसकी आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष से कम आयुवर्ग की है। भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि, संसाधनों के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यदि भारत को सतत् समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इसके लिए सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राइट्स लिमिटेड, परामर्श और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक प्रमुख संगठन होने के नाते, अपने ही तरीके से भारत की आर्थिक प्रगति की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बना हुआ है। राइट्स, सतत् आधार पर, अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रियाओं की समीक्षा और पुनरीक्षण करता है, ताकि उन्हें अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। राइट्स का ध्यान न केवल त्रुटिपूर्ण व्यवहारों और प्रथाओं को हतोत्साहित करने पर है बल्कि प्रणालीगत सुधार करने पर भी है ताकि अपनी सेवाएं प्रदान करने में दक्षता लाई जा सके।

राइट्स, इस सतर्कता बुलेटिन के माध्यम से, फील्ड स्टाफ के साथ-साथ अन्य हितधारकों को पिछले एक वर्ष में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के क्षेत्रों में उठाए गए कदमों के बारे में अगवत कराता है। बुलेटिन में केस अध्ययन भी शामिल हैं ताकि सभी इनमें निहित संदेशों को आसानी से समझ सकें।

मैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी, राइट्स और उनकी टीम को इस सतर्कता सप्ताह के आयोजन और इस सतर्कता बुलेटिन को प्रकाशित करने, साथ ही वर्षभर कंपनी के क्रियाकलापों के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अथक प्रयास के लिए बधाई देता हूँ।

(अनिल विज)  
निदेशक तकनीकी





**Anil Vij**

Integrity in public life is an essential component in establishing trust between the Government and its Citizens. In India, every year, Vigilance Awareness Week is observed to re-affirm the commitment made by all public servants, to observe the highest levels of integrity and probity in discharge of their official duties and functions.

This year, the Vigilance Awareness Week, from 26<sup>th</sup> of October to 1<sup>st</sup> November, has “**Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity**” as its theme, in keeping with the year long celebrations for the 75<sup>th</sup> year of independent India.

Integrity in public life is definitely not a one time affair but has to manifest itself in the life and conduct of a public servant at all times and situations, 24 x 7. Integrity is not just elimination of corruption and bribery etc. but goes much beyond this and definitely involves doing the right thing in the right way. Therefore, while elimination of negative behaviour is important, reinforcement and strengthening of positive behavior is also equally important.

India, at the age of 75, is still a young nation and is in the building process. Demographically as well, India is a young country, with more than half the population, being below 30 years of age. India is also one of the fastest growing economies of the world. However, along with resources, also come responsibilities. If India has to achieve its aim of continued inclusive growth, high level of integrity in public life is extremely important.

RITES Limited, being a premier organization in the consultancy and infrastructure sectors, continues to be a vital cornerstone of India’s economic progress in its own way. RITES, on a continual basis, reviews and revisits its business delivery processes, so as to make them more transparent and effective. RITES’ focus is not only on discouraging errant behaviours and practices but also to undertake systemic improvements so as to bring about efficiency in delivery of its services.

RITES, through this Vigilance bulletin, aims to educate the field staff as also other stakeholders about the steps taken in the last one year in the areas of integrity and probity. The bulletin also includes case studies so that the messages sought to be conveyed can easily be understood by all.

I would like to compliment Chief Vigilance Officer, RITES and his team for organizing this Vigilance week and for bringing out this Vigilance bulletin, as also their untiring efforts, round the year, in this vital area of running the affairs of the Company.



**(Anil Vij)**  
**Director Technical**





**बी .पी .नायक**

इस वर्ष 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है-"**स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता**"। देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "**स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता**" देश के आर्थिक विज्ञान और आर्थिक विकास के संबंध में सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार के प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं जिसका प्रमाण यह है कि सेंसेक्स 60 हजार से ऊपर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह मुख्य रूप से घरेलू खुदरा निवेशकों से आने वाला पैसा है जिससे स्टॉक ने नई ऊंचाइयां छुई हैं।

महामारी की स्थिति के बावजूद, राइट्स अपनी वित्तीय और मजबूत ऑर्डर बुक के मामले में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। इसलिए राइट्स से जुड़े भ्रष्टाचार के किसी भी मामले से बाजार में कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दावों के समय पर निपटान तथा विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए कई पहलें की गई हैं।

राइट्स सतर्कता विभाग सीवीओ के मार्गदर्शन में कई गतिविधियों का संचालन कर रहा है और सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के सिलसिले में इस सतर्कता बुलेटिन का भी प्रकाशन कर रहा है। मैं, सीवीओ और उनकी टीम को उनके प्रयासों और बुलेटिन के संकलन के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इससे राइट्स की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में कार्यरत अधिकारियों के लिए अत्यधिक व्यावहारिक मदद मिलेगी।

**(बी. पी. नायक)**  
**निदेशक वित्त**





**B. P. Nayak**

The theme of this year's Vigilance Awareness Week being observed from 26<sup>th</sup> October to 1<sup>st</sup> November 2021 is **"Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity"**. Eradication of corruption is necessary for the development of nation.

The theme of this year's Vigilance Awareness Week **"Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity"** is in line with Government's vision of Atmanirbhar Bharat in relation to the economic vision and economic development in the country. The Government's efforts are showing the results which can be seen from the fact that the Sensex has reached to the new height of above 60K. It is basically the money coming from domestic retail investors which has driven stock to new high.

Despite of the pandemic situation, RITES is making excellent progress in terms of its financials and enhanced order books therefore any case of corruption from RITES will adversely affect the company in the market. Several initiations have been taken for timely settlement of claims, payments of various kinds.

RITES Vigilance under the guidance of CVO is undertaking number of activities and is also bringing out this Vigilance Bulletin in connection with Vigilance awareness Week 2021. I congratulate CVO and his team for their efforts and compiling the bulletin. I am sure that it will be of immense practical help for the officers engaged in various business activities of RITES.

**(B. P. Nayak)**  
**Director Finance**



No. 004/VGL/18  
Government of India  
Central Vigilance Commission

\*\*\*\*\*

Satarkata Bhawan, Block-A,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi-110023.  
Dated:13th April,2004

Office Order No. 23/04/04  
(read with modification vide office Order No. 74/12/05)

**Subject: Vigilance angle – definition of.**

As you are aware, the Commission tenders advice in the cases, which involve a vigilance angle. The term “vigilance angle” has been defined in the Special Chapters for Vigilance Management in the public sector enterprises, public sector banks and public sector insurance companies. The matter with regard to bringing out greater quality and precision to the definition has been under reconsideration of the Commission. The Commission, now accordingly, has formulated a revised definition of vigilance angle as under:

**“Vigilance angle is obvious in the following acts: -**

- i. Demanding and/or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his influence with any other official.
- ii. Obtaining valuable thing, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he has or likely to have official dealings or his subordinates have official dealings or where he can exert influence.
- iii. Obtaining for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.
- iv. Possession of assets disproportionate to his known sources of income.
- v. Cases of misappropriation, forgery or cheating or other similar criminal offences.

2(a)\*\* There are, however, other irregularities where circumstances will have to be weighed carefully to take a view whether the officer's integrity is in doubt. Gross or willful negligence; recklessness in decision making; blatant violations of systems and procedures; exercise of discretion in excess, where no ostensible/public interest is evident; failure to keep the controlling authority/superiors informed in time – **these are some of the irregularities where the disciplinary authority with the help of the CVO should carefully study the case and weigh the circumstances to come to a conclusion whether there is reasonable ground to doubt the integrity of the officer concerned.**

2(b) **Any undue/ unjustified delay in the disposal of a case, perceived after considering all relevant factors, would reinforce a conclusion as to the presence of vigilance angle in a case.**

**\*\*as modified vide Office Order No. 74/12/05 dated the 21/12/05.**

3. The raison d'être of vigilance activity is not to reduce but to enhance the level of managerial efficiency and effectiveness in the organization. Commercial risk taking forms part of business. Therefore, every loss caused to the organization, either in pecuniary or non-pecuniary terms, need not necessarily become the subject matter of a vigilance inquiry. Thus, whether a person of common prudence, working within the ambit of the prescribed rules, regulations and instructions, would have taken the decision in the prevailing circumstances in the commercial/operational interests of the organization is one possible criterion for determining the bonafides of the case. A positive response to this question may indicate the existence of bonafides. A negative reply, on the other hand, might indicate their absence.
4. Absence of vigilance angle in various acts of omission and commission does not mean that the concerned official is not liable to face the consequences of his actions. **All such lapses not attracting vigilance angle would, indeed, have to be dealt with appropriately as per the disciplinary procedure under the service rules.**
5. The above definition becomes a part of the Vigilance Manual and existing Special Chapter on Public Sector Banks and Public Sector Enterprises brought out by the Commission, in supersession of the existing definition.

CVOs may bring this to the notice of all concerned.

Sd/-  
(Anjana Dube)  
Deputy Secretary

All Chief Vigilance Officers



### केस अध्ययन-1

#### क्रेता से स्पष्टीकरण नहीं लिया गया

एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि निरीक्षण इंजीनियर ने 1000 ग्राम/ एम<sup>2</sup> जिंक कोटिंग के बजाय 610 ग्राम/ एम<sup>2</sup> जिंक कोटिंग के गैल्वनाइज स्टील स्ट्रक्चर मास्ट को स्वीकार करके "अनुबंध के नियम और शर्तों" का उल्लंघन किया है।

मामले की जांच की गई और निम्नलिखित तथ्य पाए गए: -

1. अनुबंध समझौते के व्याख्यात्मक नोट में यह उल्लेख किया गया था कि 1000 ग्राम/मीटर<sup>2</sup> जिंक कोटिंग के गैल्वनाइजेशन के साथ गैल्वनाइज स्टील स्ट्रक्चर की आपूर्ति की जानी है।
2. निरीक्षण मामले के दस्तावेजों से, यह देखा गया कि जिंक कोटिंग की आवश्यकता न तो स्वीकृति पत्र (खरीदार से ठेकेदार को) में निर्दिष्ट थी और न ही ठेकेदार द्वारा आरडीएसओ प्रमाणित निर्माता को जारी किए गए क्रय आदेश में।
3. रिकॉर्ड्स में यह देखा गया कि निरीक्षण इंजीनियर ने फर्म के आंतरिक रिकॉर्ड को स्वीकार किया है जिसमें जिंक कोटिंग को 610 ग्राम/मीटर<sup>2</sup> औसत न्यूनतम दर्शाया गया है और जिंक कोटिंग के लिए केवल 610 ग्राम/मीटर<sup>2</sup> औसत न्यूनतम के साथ स्वीकृति परीक्षण किया गया है।
4. आरडीएसओ विनिर्देश संख्या ईटीआई/ओएचई/13(4/84) के अनुसार दो प्रकार की कोटिंग्स निर्दिष्ट की गई हैं- पहली उपनगरीय और हल्के प्रदूषित क्षेत्र के लिए 610 ग्राम/मीटर<sup>2</sup> के साथ और दूसरा समुद्री और रासायनिक रूप से प्रदूषित क्षेत्र के लिए 1000 ग्राम/मीटर<sup>2</sup> के साथ तथा प्रसांगिक विनिर्देश में इसका उल्लेख नहीं है कि यदि एलओए या खरीद आदेश में जिंक कोटिंग निर्दिष्ट नहीं है तो 610 ग्राम/मीटर<sup>2</sup> कोटिंग पर विचार किया जाना है।
5. चूंकि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इंजीनियर के पास उपलब्ध दस्तावेजों में जिंक कोटिंग की आवश्यकता के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी, उन्हें निरीक्षण के लिए आगे बढ़ने से पहले क्रेता से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था।
6. निरीक्षक इंजीनियर ने सामग्री को गलत तरीके से पारित किया था, जो अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार नहीं थी।

**शिक्षा:** निरीक्षण की आवश्यकता के संबंध में कोई अस्पष्टता पाए जाने पर निरीक्षण शुरू करने से पहले निरीक्षक इंजीनियर को क्रेता से स्पष्टीकरण लेना चाहिए।

### CASE STUDY-1

#### Clarification Not Taken From Purchaser

A Complaint was received that Inspecting Engineer has violated the "Terms and Condition of Contract" by accepting Galvanised Steel Structure Mast of 610 gm/m<sup>2</sup> zinc coating instead of 1000 gm/m<sup>2</sup> zinc coating.

Matter was investigated and following were observed: -

1. In the Explanatory Note of Contract Agreement it was mentioned that Galvanised Steel Structures with galvanisation of 1000 gm/m<sup>2</sup> zinc coating is to be supplied.
2. From the inspection case documents, it was observed that requirement of Zinc coating was neither specified in the Letter of Acceptance (Purchaser to Contractor) nor in the Purchase Order issued by Contractor to RDSO Approved Manufacturer.
3. In the records it was seen that Inspecting Engineer has accepted firm's internal records indicating Zinc Coating as 610 gm/m<sup>2</sup> average minimum and further conducted acceptance test for zinc coating with 610 gm/m<sup>2</sup> average minimum only.
4. RDSO specification no. ETI/OHE/13(4/84) specifies two type of coatings one with 610 gm/m<sup>2</sup> for suburban and lightly polluted area & another with 1000 gm/m<sup>2</sup> for marine and chemically polluted area and no where it is mentioned in the relevant specification that if zinc coating is not specified in LOA or Purchase order then 610 gm/m<sup>2</sup> coating is to be considered.
5. As there was no clarity in documents available with Inspecting Engineer at the time of inspection regarding type of Zinc Coating requirement, he should have asked for necessary clarification from Purchaser before proceeding for inspection.
6. Inspecting Engineer had wrongly passed the material, which was not as per the requirement of Contract agreement.

**Lesson:-** Inspecting Engineer should have to take clarification from Purchaser before start of inspection, if any ambiguity is observed regarding the inspection requirement.

## केस अध्ययन-2

### आईबीएस और निरीक्षण केस दस्तावेजों में प्रविष्टियों का हेरफेर

निरीक्षण इंजीनियरों द्वारा जारी दैनिक कार्य योजना (डीडब्ल्यूपी) और निरीक्षण प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गई हैं:-

1. राइट्स इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग एंड बिलिंग सिस्टम (आईबीएस) में अपलोड की गई तस्वीरों से यह देखा गया है कि निरीक्षण इंजीनियर ने दो अलग-अलग स्थानों पर एक ही तारीख और एक ही समय पर निरीक्षण किया है।

**निरीक्षण करने वाले इंजीनियर ने निरीक्षण किए बिना तस्वीरों की तारीख और समय में हेरफेर किया हो ऐसा लगता है।**

2. राइट्स आईबीएस के अनुसार, डिजिटल निरीक्षण प्रमाणपत्रों में विज़िट की संख्या और निरीक्षण की तिथियां, दैनिक कार्य योजना में दर्ज की गई डिफॉल्ट प्रविष्टियां हैं। कुछ मामलों में, निरीक्षण इंजीनियर ने डीडब्ल्यूपी में प्रविष्टि नहीं की है, लेकिन वे विशेष तिथियां निरीक्षण प्रमाणपत्रों में मौजूद थीं। निरीक्षण की तिथियां दैनिक कार्य योजना से मेल नहीं खा रही थीं।

**निरीक्षण इंजीनियर ने डिजिटल निरीक्षण प्रमाणपत्रों में दौरों की संख्या और निरीक्षण की तारीखों में हेरफेर किया है।**

**शिक्षा:** निरीक्षण इंजीनियर को राइट्स के आईबीएस पोर्टल में सही और सच्ची जानकारी पोस्ट करनी चाहिए।

## CASE STUDY-2

### Manipulation of entries in IBS & Inspection Case Documents.

During scrutiny of Daily Work Plan (DWP) and Inspection Certificates issued by Inspecting Engineers, the following anomalies have been observed:-

1. From the photographs uploaded in RITES Inspection Monitoring & Billing System(IBM), it has been observed that Inspecting Engineer has conducted inspection on same date and time at two different locations.

**Inspecting Engineer may have manipulated date & time of photographs without conducting Inspection.**

2. As per RITES IBM, No. of Visits and Dates of Inspection in Digital Inspection Certificates are default entries as entered in Daily Work Plan. In few cases, Inspecting Engineer has not entered DWP, but those particular dates were present in Inspection Certificates. Inspection dates were not matching with Daily Work Plan.

**Inspecting Engineer has manipulated No. of Visits and Dates of inspection in Digital Inspection Certificates.**

**Lesson:** Inspecting Engineer should post correct and true information in IBM portal of RITES.



### केस अध्ययन-3

#### विक्रेता द्वारा संशोधन सूचना में जालसाजी

आकस्मिक निवारक जांच में यह पाया गया कि क्रय आदेश/कॉल लेटर में उल्लेखित निरीक्षण स्थल पर सामग्री उपलब्ध नहीं थी। निरीक्षण इंजीनियर ने बताया कि सामग्री अलग-अलग पते पर उपलब्ध है और फर्म ने क्रय प्राधिकारी से जारी निरीक्षण के स्थान के संबंध में संशोधन सूचना (एमए) प्रस्तुत की थी।

संशोधन सूचना की समीक्षा पर निम्नलिखित पाया गया:-

1. खरीद आदेश संदर्भ का उल्लेख संशोधन सूचना में नहीं किया गया था जिसके खिलाफ यह संशोधन जारी किया गया था।
2. संशोधन सूचना में तिथि क्रय आदेश जारी करने से पहले की है।
3. डिजिटल हस्ताक्षर की तारीख संशोधन सूचना(Advice) की तारीख से अलग थी।
4. निरीक्षण निगरानी एवं बिलिंग प्रणाली (आईबीएस) में उपलब्ध क्रय आदेश से यह देखा गया कि निवारक जांच के समय निरीक्षण इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत संशोधन सूचना में उल्लिखित पता किसी और विक्रेता का है।

उपरोक्त विसंगतियों को देखने के बाद, क्रेता से क्रय आदेश और संशोधन सूचना की प्रमाणित प्रतियां भेजने का अनुरोध किया गया था।

क्रेता से प्राप्त खरीद आदेश और संशोधन सूचना की प्रमाणित प्रतियों से, निम्नलिखित पाया गया:

1. क्रेता द्वारा अलग फर्म को अलग क्रय आदेश के विरुद्ध संशोधन सूचना जारी की गई थी।
2. संशोधन की तिथि एमए पर उपलब्ध डिजिटल हस्ताक्षर तिथि के समान थी।
3. निरीक्षण के समय प्रस्तुत की गई संशोधन सूचना में दिया गया पता किसी और फर्म का है।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि फर्म ने निरीक्षण के दौरान छेड़छाड़/जाली रेलवे संशोधन सूचना प्रस्तुत की है और राइट्स निरीक्षण इंजीनियर को गुमराह किया है। राइट्स के निरीक्षण इंजीनियर ने भी संशोधन सूचना की ठीक से जांच नहीं की है।

**शिक्षा:** राइट्स के निरीक्षण इंजीनियर को निरीक्षण कार्य आरंभ करने से पहले संशोधन सूचना को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए।



### CASE STUDY-3

#### Forgery in Modification Advice By Vendor

In a Surprise Preventive check, it was observed that material was not available at the place of inspection as mentioned in purchase order/call letter. Inspecting Engineer informed that material is available at a different address and firm had submitted the Modification Advice (MA) regarding place of inspection issued from purchasing authority.

On scrutiny of modification advice, the following were observed: -

1. Purchase Order reference was not mentioned in the modification advice against which this amendment was issued.
2. Date in the modification advice is before issuance of Purchase Order.
3. Digital Signature date was different from the date of modification advice.
4. From the Purchase Order available in the Inspection Monitoring & Billing System (IBS), it was observed that address mentioned in the Modification Advice submitted by Inspecting Engineer at the time of Preventive Check belong to different vendor.

After seeing the above anomalies, the authenticated copies of Purchase Order and Modification Advice were requested from Purchaser.

From the Authenticated copies of Purchase Order and Modification Advice as received from Purchaser, the following were observed:

1. Modification advice was issued by Purchaser to different firm against different Purchase Order.
2. Date of modification was same as of digital signature date available on MA.
3. Address as mentioned in the Modification Advice submitted at the time of inspection belongs to different firm.

From the above, it is evident that firm has submitted manipulated/forged Railway Modification Advice and misguided to RITES Inspecting Engineer during inspection. RITES Inspecting Engineer has also not done scrutiny of the modification advice properly.

**Lesson:** RITES Inspecting Engineer should verify the modification advice carefully before proceeding for inspection.



## केस अध्ययन-4

### विक्रेता द्वारा कंडक्टर प्रतिरोध मीटर में हेरफेर

कंडक्टर प्रतिरोध परीक्षण में एक्सएलपीई केबल की विफलता के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आपूर्ति की गई सामग्री के लिए किए गए संयुक्त निरीक्षण में अस्वीकार्यता की पुष्टि की गई थी इसलिए अंततः सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया।

मामले की जांच की गई और निम्नलिखित पाया गया: -

1. संयुक्त निरीक्षण (जेआई) के दौरान, निर्माता अपना कैलिब्रेटेड कंडक्टर रेजिस्टेंस (सीआर) मीटर भी लाया था। लॉट मैनुफैक्चरर्स मीटर से चेक करते समय कंडक्टर रेजिस्टेंस वैल्यू को पूरा कर रहा था, लेकिन कंसाइनी द्वारा प्रदान किए गए कैलिब्रेटेड कंडक्टर रेजिस्टेंस मीटर के साथ टेस्ट करने पर यह कंडक्टर रेजिस्टेंस वैल्यू में फेल हो रहा था।

विवाद को हल करने के लिए संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में दोनों मीटरों का परीक्षण किया गया, और पाया गया कि निर्माता के मीटर में एसी रिपल वोल्टेज था, जिसके कारण मीटर कम प्रतिरोध रीडिंग (वास्तविक का लगभग आधा) का संकेत दे रहा था, इसलिए संयुक्त निरीक्षण के दौरान निष्कर्षतः रेलवे मीटर का इस्तेमाल किया गया और लॉट को रिजेक्ट कर दिया गया।

2. एक निरीक्षण के दौरान, बाहरी प्रयोगशाला में कंडक्टर प्रतिरोध परीक्षण की जांच करने के लिए निरीक्षण इंजीनियर ने केबल के दो नमूने भेजे थे. भेजे गए नमूनों में से प्रत्येक की लंबाई 5 मीटर थी, जबकि विनिर्देशानुसार नमूने न्यूनतम 10 मीटर के होने चाहिए. मीटर कंडक्टर प्रतिरोध के परीक्षण की लंबाई से यह पता चलता है कि विनिर्देशानुसार निर्दिष्ट की गई न्यूनतम लंबाई की आवश्यकता के बारे में निरीक्षण इंजीनियर को पता नहीं था।

ऊपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि :

1. फर्म के पास एक हेर-फेर किया हुआ कंडक्टर रेजिस्टेंस मीटर था ।
2. निरीक्षण इंजीनियर प्रासंगिक विनिर्देश के अनुसार सही नमूना लंबाई सुनिश्चित करने में विफल रहे।

### **शिक्षा:-**

- i) निरीक्षण इंजीनियर को उपकरण की उचित माप क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरोध की उचित सीमा वाले कैलिब्रेटर बॉक्स के साथ कंडक्टर प्रतिरोध मीटर को क्रॉस चेक करना चाहिए।
- ii) निरीक्षण इंजीनियर को प्रासंगिक विनिर्देश के अनुसार कड़ाई से कंडक्टर प्रतिरोध परीक्षण करना चाहिए।



## CASE STUDY-4

### Manipulation in Conductor Resistance Meter by Vendor

A complaint was received regarding failure of XLPE Cable in Conductor Resistance test. The material was finally rejected as rejection was confirmed in joint inspection held for the material supplied.

Matter was investigated and following were observed: -

1. During Joint inspection (JI), the manufacturer had also brought his calibrated Conductor Resistance (CR) meter. The lot was meeting conductor resistance value while checking with manufacturers meter, but it was failing in conductor resistance value when tested with calibrated conductor resistance meter provided by consignee.

To resolve the dispute both the meters were tested at a NABL accredited lab by JI committee, and it was observed that manufacturers meter was having AC ripple voltage due to which meter was indicating lower resistance reading (almost half of actual) hence JI was concluded with Railway meter and lot was rejected.

2. During one inspection, IE had sent two samples of cable for testing in outside lab for conductor resistance test. The samples drawn were having length of 5 meters each while the specification mention that samples should be of minimum 10 mtr. In length for testing conductor resistance indicating that IE was not aware of minimum length requirement specified in specification.

From the above

- i) It is evident that firm was having a manipulated Conductor Resistance meter.
- ii) Inspecting Engineer failed to ensure correct sample length as per relevant specification.

#### **Lesson: -**

- i) Inspecting Engineer should cross check Conductor Resistance meter with the Calibrator Box having appropriate range of Resistance to ensure the reasonable correctness of instrument.
- ii) Inspecting Engineer should carry out Conductor Resistance test strictly as per the relevant specification.



## केस अध्ययन-5

### रेलवे कार्यों में एम्बैंकमेंट के लिए दिशानिर्देशों और विशिष्टताओं का पालन

मुख्य तकनीकी परीक्षक/केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई गहन जांच में यह पाया गया कि एम्बैंकमेंट (Embankment) के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी एस.एम. (SM) मिट्टी के रूप में वर्गीकृत थी। इसके अलावा, भारी एक्सल लोड फॉर्मेशन डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों और विशिष्टताओं के अनुसार एस.एम. मिट्टी को एस.क्यू.2 (SQ2) के रूप में परिभाषित किया गया है और ऐसी मिट्टी के लिए 32.5 टन एक्सल लोड पर ब्लैकेटिंग लेयर की मोटाई की आवश्यकता 600mm होनी चाहिए और जिओ-टेक्सटाइल (Geo-Textile) भी ब्लैकेटिंग लेयर के नीचे प्रदान की जानी चाहिए, हालांकि इस कार्य में जिओ-टेक्सटाइल प्रदान नहीं किया गया था।

रेलवे परियोजनाओं के कार्य से संबंधित सभी तकनीकी अधिकारियों को ब्लैकेटिंग लेयर निर्धारित करते समय संबंधित दिशानिर्देशों और विशिष्टताओं का पालन करना चाहिए।

## Case Study-5

### Adherence to Guidelines and Specifications for earthen embankment works of Railways

In a certain Intensive Examination of work by Chief Technical Examiner/Central Vigilance Commission, it was pointed out that the soil used for embankment was classified as SM soil. Further, as per Guidelines & Specification for design of formation for heavy Axle load ; the quality class of SM soil is defined as SQ2 and for such soil the thickness requirement of blanketing material for 32.5T Axle load should be 600mm and Geo-textile should also be provided below blanketing layer, however in that work no Geo-textile was provided below the blanketing layer.

All technical officers dealing with Railway Projects must adhere to Guidelines and Specifications while adopting thickness of blanketing layer.





### केस अध्ययन-6

## अनुबंध के निरस्तीकरण के समय उन सामग्रियों की जब्ती जिनके लिए सुरक्षित अग्रिम भुगतान किया गया

मुख्य तकनीकी परीक्षक/केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई गहन जांच में यह पाया गया कि अनुबंध के निरस्तीकरण के समय ठेकेदार के प्रति लगभग 11 करोड़ रुपये का सुरक्षित अग्रिम बकाया था। सामग्री अर्थात् स्टील सरिया, जिसके लिए सुरक्षित अग्रिम भुगतान किया गया था, साइट के विभिन्न स्थानों पर पड़ा था। ठेका निरस्त होने के बाद ठेकेदार ने साइट से सारी सामग्री ले ली और बैंक गारंटी के नकदीकरण पर भी रोक लगाने का आदेश न्यायालय द्वारा दे दिया गया। बाद में, ठेकेदार से सभी वसूली करने के बाद भी लगभग रु 12.0 करोड़ ठेकेदार से वसूली के लिए लंबित थे जो कि अब न्यायालय से स्टे हटने के बाद ही वसूले जा सकते हैं।

साइट पर कार्यरत सभी अधिकारियों को साइट पर सामग्री की जब्ती के लिए उचित सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए, यदि कुछ कारणों से यह संभव नहीं है तो तत्काल उचित अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए।

### Case Study-6

## Confiscation of Materials against which Secured advance paid at the time of rescission of Contract

In a certain Intensive Examination of work by Chief Technical Examiner/Central Vigilance Commission, it was pointed out that Secured advance of approximately Rs.11 Crores was outstanding towards the contractor at the time of rescission of the contract. The material i.e., reinforcement steel against which the secured advance paid was lying at various locations of site. After the termination of contract, the contractor took away the material from the site, also stay on encashment of BGs was ordered by the court of law. Later, after all the recoveries from the contractor an amount of approximately Rs. 12.0 Crores was pending for recovery from the contractor and same can be done after stay get vacated from the court.

Field organization should take appropriate proactive action for confiscation of material at site, if not possible due to certain reasons same must be informed to appropriate authorities, immediately.



## केस अध्ययन-7

### संगठन छोड़ने वाले कर्मचारियों की आईटी सेवाओं को अक्षम करने का प्रक्रिया आदेश

कर्मचारियों के कंपनी से अलग होने के बाद विभिन्न आईटी सेवाओं जैसे ई.मेल, एसएपी, कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) तथा जेम पोर्टल पर प्रवेश को अक्षम करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं के संबंध में सतर्कता शाखा द्वारा एक निवारक जांच की गई, ताकि सरकारी आईटी सेवाओं के किसी भी अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके।

तीन महीनों (सितम्बर – अक्टूबर 2020) के रिकॉर्ड की जांच करने पर, उस अवधि के दौरान अलग हुए कर्मचारियों की संख्या और उन कर्मचारियों के डेटा के बीच बेमेल पाया गया, जिनकी आईटी सेवाएं अक्षम की गई थीं। परिभाषित प्रक्रियाओं या दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति के कारण, संबंधित एचआर और आईटी टीमों के बीच स्पष्टता और समन्वय की कमी पाई गई।

विजिलेंस की सलाह के अनुसार, कर्मचारियों के संगठन छोड़ने के मामलों में ईमेल, एसएपी, ईएसएस और जीईएम पोर्टल खातों तक पहुंच को अक्षम करने के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया आदेश कार्यालय आदेश सं. पीपी/49/2021 द्वारा जारी किया गया है।

#### प्रभाव और लाभ :

- सरकारी आईटी सेवाओं तक अनधिकृत पहुंच पर रोक।
- मानव संसाधन और आईटी टीमों के बीच समन्वय।
- परिभाषित प्रक्रियाएं संबंधित अधिकारियों की भूमिकाएं, समयसीमा और जिम्मेदारी स्थापित करती हैं। खामियों और जिम्मेदारी का पारदर्शी रूप से पता लगाया जा सकता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है।
- अलग किए गए कर्मचारियों को आईटी सुविधाओं के समय पर वापस लेने से आईटी संसाधनों की अनुकूल उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

## Case Study-7

### Procedure Order to disable IT services to employees leaving the organisation

A Preventive Check was conducted by Vigilance regarding existing Procedures in place for disabling access to various IT services viz. Email, SAP, Employee Self Service (ESS) & Gem Portal after the separation of employee from the company. The purpose was to prevent any unauthorised use of Government IT services.

On scrutiny of records of three months (September – October 2020), mismatch was found between the number of employees separated during that period with that to the data of employees whose IT services were disabled. Due to the absence of defined Procedures or Guidelines, lack of clarity and coordination between concerned HR and IT teams was noted.

As per Vigilance advise, detailed procedure order was issued and implemented vide Office order no. PP/49/2021 with regard to disabling access to Emails, SAP, ESS & GeM portal accounts in cases of employees leaving the organisation.

#### Impact and Benefits:

- Devoid unauthorised access to Government IT services.
- Co-ordination between HR & IT teams.
- Defined procedures establish roles, timelines, and responsibility of concerned officials. The lapses and responsibility can be transparently traced and fixed.
- Optimization of available IT resources by timely revocation of IT facilities to the separated employees.



## Procurement of Services and Works

Public procurement refers to procurement of external resources needed by the central or state governments as well as entities under their control using public funds. The officials have been doing procurement (purchase) of such resources which can be classified as goods, services and works. Such public procurement necessitates the officials to follow prescribed procedures to avoid any embezzlement of public funds while procuring desired quality goods, services or works at competitive prices.

The fundamental and most important principle of procurement is fairness and transparency. General Financial Rules (GFR), which is a compendium of general provisions to be followed by the public entities while dealing with matters of financial nature, elaborate and specify detailed procedures to implement the principle of transparency in public procurements. The important aspects of transparency concern availability and clarity of information regarding requirements to all prospective bidders, submission and opening of proposals, qualification requirements and eligibility of bidders, criteria of evaluation of proposals and selection of successful bidder for delivering the intended goods, services or works. Transparency in public procurement also ensures a level playing field resulting in fair competition among prospective bidders.

There are various methods for procurement of consulting services viz. Quality Cost Based Selection (QCBS), Fixed Budget Based Selection (FBS), Quality Based Selection (QBS), Consultant's Qualifications Based Selection (CQS), Least Cost Based Selection (LCS), and Direct Selection. All these selection methods have advantages and disadvantages one over other in terms of complexity of the Project.

Under QCBS, selection of the consulting firm is done by an Employer based on the quality of the technical proposal and the cost of the services offered by the competing consulting firms. The Employer through Request for Proposals (RFP) document specifies the minimum score for the technical Proposals and assigns relative weights to the quality of the technical proposal and cost depending on the nature of the assignment. The technically qualified consulting firm with highest combined (quality and cost) score is considered most preferred for award of the consulting services. In India, various entities such as National Highways Authority of India (NHAI), Inland Waterways Authority of India (IWAI), Metro Rail Corporations, and Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) etc. widely use QCBS method for procurement of consulting services. Generally, eighty percent weightage is assigned to technical proposals and relatively twenty percentage weightage is assigned to financial proposals. However, it has been observed that various small-time and despairing bidders offer abnormally low and unworkable financial proposals leading to an imbalanced competition. In such scenarios the competent bidders are left out and ultimately the quality of consulting services gets badly affected in terms of substandard deliverables and unreasonable delays.



In order to ensure up to the mark delivery standards of consulting services, it is prudent to assign higher weightage to technical proposals which mostly countervails effects of low financial proposals and in turn helps in keeping bidders at bay who induce imbalanced competition. Another way of weeding out such bidders is to reject those financial proposals which are quoted fifteen or twenty percent below average of all financial proposals. Excessively higher financial proposals may also be eliminated by introducing upper bracket of fifteen or twenty percent above average of all financial proposals.

In procurement of consulting services for the Multilateral Development Banks (MDBs) such as Asian Development Bank (ADB), World Bank (WB), and African Development Bank (AfDB) etc., generally QCBS method is adopted by the Employer/Borrower. Especially in ADB funded Projects, QCBS is used with relative weightage of technical proposals as ninety percent and ten percent for financial proposals, which by and large ensures selection of a technically competent consulting firm. However, in order avoid high financial proposals, the budget of consulting services is also disclosed to all the participating bidders with a condition that the financial proposals exceeding the budget would be rejected. This method of selection has been adopted In ADB funded projects in various Asian, South-East Asian and Pacific region countries like Bangladesh, Philippines and Papua New Guinea.

Like QCBS, under FBS also the selection of consulting firm is done based on the quality of the technical proposal and the cost of the services. However, the consulting firm with highest technical score and cost of services not exceeding the fixed budget is considered most preferred for award of consulting services. FBS is generally appropriate for simple consulting services with precisely defined scope for which budget is reasonably estimated and sufficient. FBS is not widely used for big and complex Projects.

Under CQS method, the Employer invites Expressions of Interest (EOI) by providing the terms of reference of desired services from the consulting firms. From the firms that have submitted an EOI, the Employer selects the firm with the best qualifications and relevant experience and invites it to submit its technical and financial Proposals for negotiations and award of consulting services. CQS is appropriate for small assignments or emergency situations in which preparing and evaluating competitive proposals is not justified.

Under QBS, the highest technically qualified consultancy firm is considered most preferred, and its financial proposal is opened for negotiations and in turn award. QBS method is appropriate for complex or highly specialized assignments for which it is difficult to define precise Terms of Reference (TOR) and the input required from the firm. MDBs have been resorting to CQS or QBS methods of selection of consulting firms for projects demanding specialized technical inputs.

Direct selection (single-source or sole-source selection) refers to approaching and negotiating with only one consulting firm. This selection method may be appropriate when only one firm is qualified, a firm has experience of exceptional worth for the assignment, or there is justification to use a preferred firm. Direct selection of consulting services is not commonly used.



LCS method also considers the quality of the technical proposal and the cost of the services. However, the consulting firm with meeting the minimum technical score and lowest cost of services is considered most preferred for award of consulting services. LCS is generally appropriate for assignments of a standard or routine nature (such as engineering designs of non-complex Works), for which well-established practices and standards exist.

Unlike consulting services, procurement of works is generally done on Least Cost basis by inviting competitive bids from the bidders. For high value works, both technical and financial bids are invited simultaneously. Sometimes, pre-qualification is also first done to shortlist the potential contractors capable of carrying out the works satisfactorily. Financial bids of only technically qualified bidders are opened, and the work is awarded to the bidder offering the lowest cost. Selection of Contractors on least cost basis ensures lowest price, however, it has its own disadvantages for not factoring in quality parameters. The Contractor who offers the lowest cost may not deliver the desired quality outputs in scheduled time due to its limitations due to not being technically competent enough or financial constraints etc. In such scenarios, the Employer ends up paying much more for the works mainly due to execution delays and cost overruns.



In recent Covid-19 times, the Government of India relaxed or lowered the qualification requirements to promote wider participation by bidders including small-timers. However, it proved to be not giving overwhelming outcomes. According to data from the Ministry of Statistics and Programme Implementation, among Projects worth INR 150 crore or more, as many as 483 have witnessed cost overrun of over INR 4.43 lakh crore. Of the 1,781 projects being monitored, 483 reported costs overrun while 504 were delayed. It is not that such cost overruns or time overruns are primarily due to award of works to lowest bidders; however, it is one of the main factors.

The procuring entities may adopt various ways and means to weed out the non-serious bidders by demanding justification of abnormally low costs and also additional performance securities from the lowest bidder. Apart from this, QCBS method may also be adopted by assigning suitable weightage for technical proposals of the bidders. Internationally fifty to sixty percent weightage is assigned to the technical proposals for selecting a bidder under QCBS. It ensures that a competent bidder is selected even if it does not offer the lowest cost. Giving more weightage to technical aspects of the bidder would expectedly make sure execution of works duly avoiding time and cost overruns.

Finally, the e-Procurement deserves special mention as it scores over manual mode of procurement in many ways. The e-Procurement is an automated process in an online web-based real-time environment, which resolves many of the constraints and delays of manual mode procurement. In India, most of the public entities have switched over to e-Procurement mode for procuring goods, services and works.

\*\*\*

Vijai Kishore,  
ED (Transport Infrastructure)  
&  
Satyendra, SDGM (HW)





## Independent India @ 75: Self-reliance with integrity

### Introduction:

As we know, the Central Vigilance Commission which has a special responsibility under para 3(v) of Government of India Resolution no 371/20/99/AVD-III dated 4.4.1999, declared that the week beginning from 31st October every year shall be observed as the Vigilance Awareness Week. The significance of 31st October is that it is the birthday of the Bismarck of India, Sardar Vallabhbhai Patel, who represents the best values in the Indian tradition so far as governance is concerned, and was also a shining example of probity in public life.

“Vigilance Awareness Week” is being observed to encourage all stakeholders to collectively participate in the preventive vigilance measures, fight against corruption and raise public awareness. The theme for this year is “**Independent India @ 75: Self-reliance with integrity**” which is the most relevant for deliberations to make every citizen to understand that it is need of the hour for the country’s growth in light of various challenges posed by pandemic situations and to accelerate current economic recovery process.

### What is Self-reliance?

The self-reliance gives confidence to try new things innovatively to produce unique results that keeps us apart from rest of the world. The results accrue from self-reliance are:

- Become truly fulfilled and content
- Become empowered
- Cultivate a strong character
- Develop strength
- Discover the unique gifts that want to be realized
- Discover an inner peace
- Elimination of regret
- It is in being courageous that destiny can be lived
- Reach full potential
- Step into greatness
- The struggles will result in more knowledge, more strength and more contentment

### The meaning of Integrity:

Integrity means always doing what is right and good, regardless of the immediate consequences and also being righteous from the very depth of our soul, not only in our actions but, more importantly, in our thoughts and in our hearts.

### Independent India @ 75:

India is one of the most powerful country globally with 1.39 billion people which accounts nearly 17.7% of world’s population, among which 34.33 % are youths. Dr. A.P.J. Abdul Kalam ji the past most popular president of India fuelled the minds of young people to dream to make our country the super power in the world. Today, our prime minister Shri. Narendra Modi ji government policy has clear vision towards making the dream to become reality **through self-reliance with integrity.**



After independence Indian governments have formed policies and implemented them through various programmes, as a result of which today our country @ 75 has the following outstanding credentials and achieved the status of:

- 3<sup>rd</sup> Largest economy (PPP) \$ 11.5 trillion
- 5<sup>th</sup> Largest economy (Nominal) \$ 3.3 trillion
- 4<sup>th</sup> Most powerful country in the world
- 2<sup>nd</sup> largest force in the world
- More than 2.1 million reserve personnel
- More than 1.4 million active personnel
- One of the most powerful nuclear weapons countries. AGNI 6 missile range 12000 KM
- A country with anti-satellite weapons. A country that can destroy any countries satellites.
- 4<sup>th</sup> most powerful and advance defence system
- ISRO the 4<sup>th</sup> most successful and 5<sup>th</sup> biggest space agency
- 3<sup>rd</sup> billionaire country with 170 billionaires
- 3<sup>rd</sup> largest manufacturer of the world
- 2<sup>nd</sup> largest smart phone producer
- 4<sup>th</sup> largest car producer
- 2<sup>nd</sup> largest steel producer
- 3<sup>rd</sup> largest electricity producer
- 2<sup>nd</sup> largest textile producer
- Largest spice producer
- One of the best IT industries. More than \$ 225 billion revenue
- 5<sup>th</sup> largest foreign exchange reserves \$ 520 billions
- Bollywood 3<sup>rd</sup> largest film industry
- A country with more than 600 million smart phone users
- More than 600 million internet users
- 2<sup>nd</sup> rank in the world in doctors, engineers & scientists
- 36% scientists of NASA are Indians
- 34% engineers of Microsoft are Indians
- 28% engineers of IBM are Indians
- The world's top companies CEO are Indians. Sundar Pitchai the CEO of google, Satya Nadella the CEO of Microsoft, Arvind Krishna the CEO of IBM, Rajeev Suri the CEO of NOKIA, Ajaypal Singh Banga the CEO of Mastercard, Sanjay Mehrotra the CEO of SanDisk, Shantanu Narayen the CEO of Adobe, Dinesh Paliwal the CEO of HARMAN.
- A youngest country having average age of 29 years.
- 17 of the 20 fastest growing cities in the world are from India.
- World's rising economy
- Estimated 3<sup>rd</sup> largest economy in world by 2025 with \$ 5.9 trillion
- Estimated World's largest PPP economy by 2050 (\$ 85.97 trillion)
- Working on the world's some mega project
- Constructing modern infrastructure by 2025 cost \$ 1.5 trillion



- Chennai to Bangalore industrial corridor investment \$ 181 billion
- SAGARMALA project cost \$ 130 billion
- Building new and modern Ports
- 100 SMART cities projects cost \$ 102 billion
- DMIC project the world's largest corridor project cost \$ 100 billion
- Largest number of projects under construction in the world
- Largest number of skyscrapers under construction in the world
- Under construction, new and modern greenfield cities (DHOLERA SIR CITY, GIFT CITY, AMRAVATI CITY)

With above credentials undoubtably India @ 75 is the rising superpower in the world.

### **RITES contribution to Vigil Independent India:**

RITES is engaged primarily in transport infrastructure sector with diversified port-portfolio under Consultancy, Turn key projects, Leasing, exports & Power Procurement business segments.

The National Infrastructure Pipeline (NIP), the National Rail Plan-2030 and various reforms in the transport infrastructure sector define a path for providing world-class infrastructure across India. Driving the progress, the Indian Railways is making holistic improvements across areas such as high-speed travel, electrification, safety, track modernization (building double track railway lines, switching from one track gauge to another, and new lines), signalling systems, capacity increase and use of renewable energy for which RITES is one of the major prime movers.

RITES has received its highest-ever order of Rs. 4027 Crore recently for executing turnkey project which includes the three new line projects - Belgam-Dharwad via Kittur, Shimoga-Shikaripura-Ranebennur and Tumkur-Devangree via Chitradurga. This is a testimony that the RITES is falling in line with the progress of the nation.

RITES is now striding towards expediting project execution and exports supply to overcome Covid-induced uncertainties. With the recent award of many infrastructure projects and successful project execution strengthen RITES position as a total transport infrastructure solution provider. The market forecast for large infrastructure projects is promising, courtesy the expected economic stimulus packages and an investment backlog within the infrastructure sector. Thus, RITES has positioned itself for securing meaningful consultancy role for complex, diverse, critical and mega infrastructure projects in India and abroad. RITES is enhancing its expertise and profile by forming consortiums/JVs for few projects to exploit the core strength of partners to benefit the customers. RITES focus on customisation of meter-gauge and broad-gauge rolling stock and product diversification to cape and standard gauge rolling stock market creates large potential for exports. Several countries in Africa and Asia are looking at the Railways with renewed interest which makes times ahead promising for RITES in export business.

Thus, RITES drives the progress of nation with absolute self-reliance with integrity.



### **RITES- Quality Assurance Division's contribution:**

RITES- QA division plays vital role in ensuring quality of material being supplied to all Railway and Non-Railway customers. In order to bring in transparency and to avoid bias the effective monitoring and control system has been put in place, among which the digitization is one of the major steps.

Digitization enabled:

1. For the customers:

- On-line call registration by vendor.
- Automatic call marking.
- Feedback to vendors on details of nominated inspecting engineer, controlling manager, inspection schedule and inspection protocol.
- Issue of digital Inspection Certificate.
- Real time monitoring of inspection status by stake holders (Controlling Managers, Purchasers, Consignees, Vigilance etc.)
- Issue of paperless bill to Railways i.e. Digital Billing.

2. For the employees:

- Inspecting Engineers are equipped with modern digital infrastructure including Laptop, and Camera etc.
- Use of standard inspection test plans.
- Upgrading the skills of Inspecting Engineers by providing Training relevant to their work. Preparation of product inspection related Instructional videos for guidance of Inspecting Engineers.
- Online E-Learning Modules for inspecting engineers.

For transparency & efficiency of day-to-day operations, reduce paper use and maintain business continuity and enable remote working, especially during the Covid-induced lockdown, several key initiatives have been taken by Quality Assurance division. E-office, SAP-based Enterprise Resource Planning (ERP), e-procurement for works through "GEM- Portal", mobile app for third-party inspection, inspection through video-conferencing, etc. have been made effective.

### **Conclusion:**

To summarise, our country is progressing steadily in all emerging areas for serving the society by the people working productively with enthusiasm and keen to innovate new things to lead the progress with the development of new products and services inculcating the culture of **self-reliance with integrity**.

**K.CHANDRASEKAR**  
**General Manager/ QA**





## भ्रष्टाचार : लालच, जरूरत या मज़बूरी

**“पृथ्वी सभी लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन सबके लालच को पूरा करने के लिए नहीं” - महात्मा गांधी**

भ्रष्टाचार क्या है ? इसे हम अपनी तृष्णाओं से उत्पन्न लालच का नाम दें या हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिये जरूरत कहें या तंत्र के कार्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए मज़बूरी की परिभाषा दें। इनमें से किसी भी एक कथन को सार्वभौमिक कहना ग़लत होगा। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न-विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न उक्तियां सही साबित हो सकती हैं।

लालच सभी भ्रष्टाचारों की जननी है, चाहे आप इसका सामना सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय में करें, ट्रेन से यात्रा करते समय, अपने करों का भुगतान करते हुए, सरकारी अस्पताल में, सड़क पर गाड़ी चलाते समय या अखबारों में पर पढ़ते समय करें। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि लालच एक अस्वीकार्य मानवीय मूर्खता है, जो हम में से अधिकांश में एक निश्चित सीमा तक मौजूद है। कुछ मामलों में, यह सिर्फ सामान्य प्राकृतिक लालच है, जबकि अन्य में यह अतृप्त है। लालच भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है जो निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति या सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग है।

युगों से शास्त्रों और ऋषियों ने दोषों और गुणों के बारे में बात की है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे सभी दोषों में से सबसे खतरनाक और सूक्ष्म प्रकृति में 'लोभ' है। कहते हैं लोभ एक ऐसी भूख है जो कभी तृप्त नहीं होती। जब हमारी भूख शांत हो जाती है तो हमारी भोजन की इच्छा समाप्त हो जाती है, उद्देश्य प्राप्त होने पर हमारा क्रोध भी कम हो जाता है, लेकिन लालच मन में एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर देता है जो पूरी दुनिया का राज्य प्राप्त करने पर भी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए, यह एक प्रवृत्ति है, जो धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में उत्पन्न होती है और जो सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है।

तो, क्या इसका मतलब यह है कि धन के महत्व को नहीं पहचानना चाहिए और जीवन भर गरीब रहना चाहिए? जरूरी नहीं है। वास्तव में आवश्यकता यह है कि धन की एक पूर्ण और स्पष्ट तस्वीर बनाई जाए और धन की विशेषताओं की सही धारणा बनाई जाए ताकि लोगों को इसके बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण मिल सके। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे सभी दृष्टिकोण और प्रवृत्तियां हमारे विश्वासों से उत्पन्न होती हैं; इसलिए, यदि हम चाहते हैं कि समाज बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त हो तो हमें सही प्रकार की मान्यताएं रखनी चाहिए। इस बात से कोई इंकार नहीं है कि जीविका के लिए धन का अर्जन आवश्यक है, लेकिन हमें इसके लाभों के बारे में अतिवादी दृष्टिकोण नहीं लेना चाहिए और नकारात्मक झुकावों को ध्यान में रखना चाहिए। धन का संचय न केवल कई बुरी प्रवृत्तियों को जन्म देता है बल्कि शांति और खुशी को भी नष्ट कर देता है।

हालांकि, लोगों का मानना है कि मनुष्य में धन और उसके फल की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि धन कमाने की यह प्रवृत्ति अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देती है जो आत्म-विनाशकारी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन और उसका संचय मनुष्य की प्राथमिक जरूरतों में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस प्रवृत्ति के साथ ईमानदारी, समाज की भलाई और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अतः धन के लाभों को लालच के खतरों से नहीं छीनना चाहिए। आत्मसंयम से संतुलन बनाना होगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा और वास्तविक अर्थों में एक वैध और शांतिपूर्ण समाज होगा।



“भ्रष्टाचार सभी को प्रभावित करता है और सभी को इससे लड़ने की जरूरत है”

रोज़मर्रा की कई परिस्थितियाँ हमारी सत्यनिष्ठा और नैतिक निर्णय को चुनौती देती हैं। भ्रष्टाचार का बीज बचपन और बच्चे के पालन-पोषण में निहित है, जब उनकी सभी अच्छी या बुरी आदतें उनमें शामिल हो जाती हैं। हम वही काटते हैं, जो हम बोते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर घर और स्कूल में बचपन का प्रशिक्षण मूल्य आधारित हो, तो हमारे समाज में इतने ऊंचे-ऊंचे भ्रष्ट नहीं होंगे।

अब भ्रष्टाचार चाहे लालच हो, जरूरत हो या फिर मज़बूरी ही क्यों ना हो, इससे सभी मायने में लड़ना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि यह मानव तंत्र में कैंसर की तरह है। कैंसर की तरह यह प्रणाली को धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से अंदर से खा रहा है। भ्रष्टाचार संक्रामक है। एक कार्यालय में, यदि पंद्रह लोग काम कर रहे हैं, तो एक या दो भ्रष्ट पूरे विभाग को भ्रष्ट कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और काले धन की उत्पत्ति हमारे समाज के भीतर कैंसर की तरह गहराई तक जा चुकी है। और कैंसर को लंबे समय तक विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो काफी दर्दनाक होता है, और इसलिए हमें इसे खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा।

हमारे समाज में समस्या भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में ज्ञान या समझ की कमी नहीं है बल्कि ऐसी प्रथाओं के खिलाफ खड़े होने के साहस की कमी है। दूसरों को निशाना बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपने बारे में क्या? हमें यह समझना होगा कि व्यवस्था भ्रष्ट है क्योंकि हम भी भ्रष्ट हैं। पहले हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम दूसरों में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरों के गलत कामों की ओर उंगली उठाने का यह बहुत पुराना तरीका है। लेकिन कोई अपना चरित्र जांचने को तैयार नहीं है। क्या वाकई हम अपने समाज से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हां है, तो हमें दूसरों से करने के लिए कहने के बजाय खुद से शुरुआत करनी होगी। पहले हमें बदलना होगा और उसके बाद ही हम दूसरों में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। हमें यह साबित करना चाहिए कि हम सही हैं, तभी हम दूसरों को इसका पालन करने के लिए कह सकते हैं।

भ्रष्टाचार जैसी बुराइयाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? यह कभी न खत्म होने वाले लालच से आता है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज की लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़नी होगी और इसे 'मैं क्या दे सकता हूँ' की भावना से बदलना होगा।  
- ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

**बी एस सी आदित्य सिंह दिनकर,**  
**सहायक प्रबंधक (यांत्रिक),**  
**गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग,**  
**राइट्स लिमिटेड (उत्तरी क्षेत्र निरीक्षण कार्यालय)**



## सत्यानिष्ठा से आत्मनिर्भर भारत

बच्चे की प्रथम पाठशाला की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है ।  
अच्छे संस्कारों से भर कर उसके भविष्य का निर्माण जो करती है ॥  
एक मां जिसने जन्म दिया, एक मां भारत माता है ।  
इस धरती पर जन्म लिया, खेले, खाये यही हमारी भाग्य विधाता है ।  
नमन वंदना उन गुरुवर की जिन्होंने स्वच्छ आचरण और कर्मणता का ज्ञान दिया ।  
सत्यानिष्ठा से कर्तव्यों का पालन करने हेतु आत्मबल का निर्माण किया ॥  
अच्छे संस्कार, आचरण एवं सत्यानिष्ठ नागरिक ही देश के निर्माण में तत्पर रहता है ।  
अपने कठिन परिश्रम एवं अच्छे कृत्यों से देश तस्वीर बदल देता है ॥  
इस पावन भारत भूमि में कई महापुरुषों ने जन्म लिया ।  
अपना सब कुछ न्योछावर करके देश पर अपना बलिदान दिया ॥  
शहीद भगत सिंह, आजाद, राजगुरु आदि कई बलिदानी थे ।  
देश की खातिर फांसी झूले वे अभिमानी ऐसे थे ॥  
बल्लभ भाई महा पुरुष ऐसे वीर निराले थे ।  
नेता जी जैसे अनेक वीर देश पर मर-मिटने वाले थे ॥  
सत्यानिष्ठा से ओतप्रोत ऐसे महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया ।  
शास्त्री जी जैसे भारत के आदिनायकों ने अपना योगदान दिया ॥  
धन संपत्ति आदि सब कुछ यहीं पर रह जायेगी ।  
अच्छे कर्मों से ही अपने नाम जग में अमर कर जाओगे ॥  
विकासशील भारत बदल रहा है, विकास की रस धारों में ।  
स्वयं आत्मनिर्भर होने के पथ पर अग्रसर है विश्व बाजारों में ॥  
शास्त्र एवं वेदों की रिचाओं से विश्व गुरु बनने का सपना एक सजाया है ।  
इस कृतिमान को सृजन करने का सही समय अब आया है । ।  
भारत का जन गण ने मन में अब यह ठाना है ।  
ज्ञान दीप से भारत मां का, विश्व भर में नई कृति पताका फहराना है ॥  
जब भारत का हर जन गण होगा सत्य निष्ठ और कर्मठ योगी ।  
सत्यानिष्ठा से आत्मनिर्भर भारत तभी कल्पना पूरी होगी ॥

जय हिन्द जय भारत

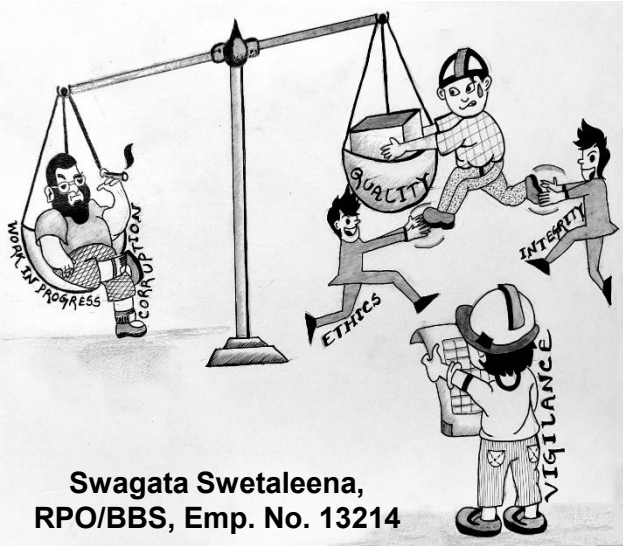
(रणबीर सिंह मल्ल)

वरिष्ठ सहायक/सतर्कता





# Cartoon Corner



Swagata Swetaleena,  
RPO/BBS, Emp. No. 13214



ELIMINATE TOGETHER CORRUPTION STAIN  
 MAKE INDIA INVINCIBLE AND GREAT AGAIN

SHIVAM KRISHNATRAY (12825), ASSISTANT MANAGER (MECH.)



## भ्रष्टाचार



आजकल हर जगह क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार,  
कभी तो जागेगा मानव मन, लिए बैठा हूँ यह आस,  
मेहनती, ईमानदार, सत्यवादी हो जाते लाचार,  
हे मानव जन जागो जागो लेने दो सभी को  
अपने मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा के बल पर  
अपनी जगह, अपना अधिकार.....।

आजकल हर जगह क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार.....  
कभी तो जागेगा मानव मन, लिए बैठा हूँ यह आस.....  
भ्रष्टाचारी के बल पर छीनो ना किसी की  
जीविका, ना किसी का मकान,  
सच्चाई के दम पर आप भी खुश रहो और  
खुश रहने दो यह सारा संसार.....।

आजकल हर जगह क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार.....  
कभी तो जागेगा मानव मन, लिए बैठा हूँ यह आस.....  
भ्रष्टाचार महामारी की तरह फैल रही है,  
आगे बढ़ो अब हे प्रिये मानव जन  
सब मिलजुल कर अपने देशहित में अपने  
कर्मपथ पर सच्चे मन से आगे बढ़ो और  
मिटा दो भ्रष्टाचार का नामोनिशान.....।

“रविकांत शर्मा”  
सहायक अभियंता (राजमार्ग प्रभाग)  
कर्मचारी संख्या - 200272





मनुष्यों का न्यायिकार भ्रष्टाचार, शष्नीति का बड़ा लक्ष्यकार भ्रष्टाचार आम आदमी पर अत्याचार भ्रष्टाचार आपदा ने अक्सर की अभिलाषा भ्रष्टाचार की है परिभाषा.  
मानवता हो रही है सुप्त भ्रष्टाचार का कुँवा यह रूप  
नैतिकता का हनन, स्वार्थ की पूर्ति भ्रष्टाचार की कुँवी शष्नीति  
जहाँ धर्म वही लूट, जहाँ न्याय वहाँ धूल, व्यक्ति का विकास तो आधा  
भ्रष्टाचार है एक मात्र बाधा, बोधो का हो रहा त्यागार्थन है जिसका बदल  
स्त्रा की भ्रुव भ्रष्टाचार की पाली  
वाद का ग्लान उम्मीदों से स्वार्थ  
साधो की कीमत लग जाती है अस्पतालो मे  
मरेते बेवस भ्रष्टाचार के पालो में.

# कविता भ्रष्टाचार का व्यवहार



जब कुझती है, धन की त्यास तन जलते है  
शष्मानो में,  
शिक्षा स्वीदा जारी है शिवत की पाठशालो में  
भ्रष्टाचार की बिन्द समस्या दब कर रह जाती है  
दिलो मे  
कर्म तले पीस जाते किसान भाई  
फिर श्री मुनाफारवारी की होती है जम के कमाई,  
प्रशासन करे कुशासन से आम आदमी की जम्बुड़ी  
भ्रष्टाचार करता है इतनी  
जरूरत पूरी  
लेकिन कुझाई कितनी श्री फल-फूल जाए  
सच्चाई की आग ठले जला देती है  
तो आओ उठो सभी जागो  
सभी उठाए भ्रष्टाचार की काठी  
ईमानदारी की शिक्षा  
है वह याही

## “भ्रष्टाचार को भगाए देश को आगे बढ़ाए”

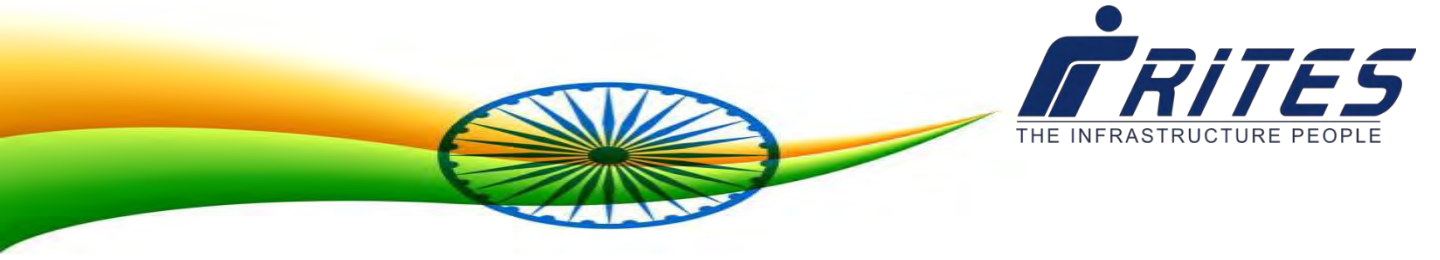


नाम - नेहा साह  
सं. - 103683  
पद :- लक्ष्मी  
सहायक

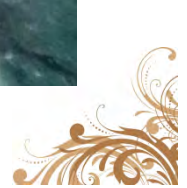
कार्यलय: गुणवत्ता व  
आभ्युत्थान मध्य  
दोतीय कार्यलय, भिवर







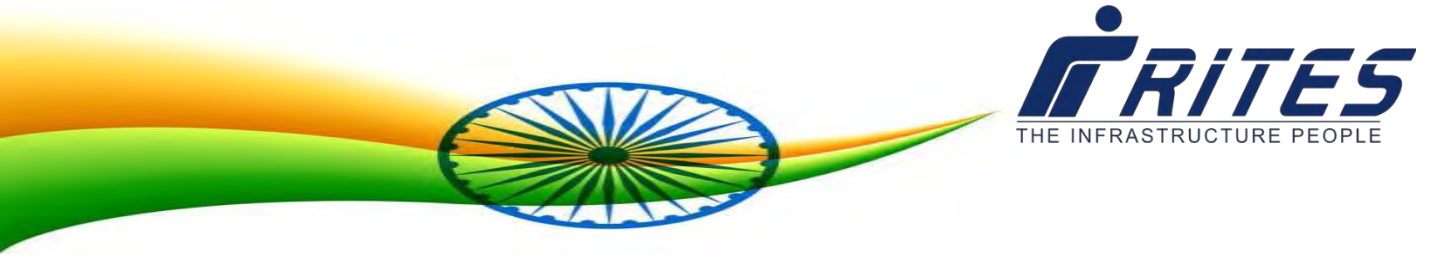
## RITES officials taking “Integrity Pledge” at RITES Corporate on 26<sup>th</sup> October 2021





## RITES officials at Regional Project & Inspection Offices taking “Integrity Pledge” on 26.10.2021



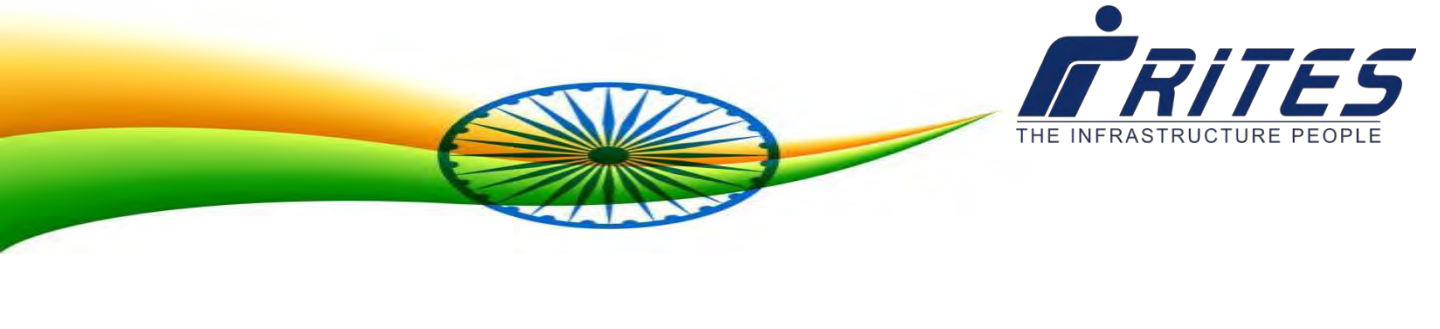


## Vigilance Activities



**Vendors & IEs Meet at RITES/ERIO/Kolkata  
on 5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> October 2021**





**Celebration of Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day)  
on 31<sup>st</sup> October 2021 at RITES Corporate Office, Gurugram.**





**GRAM SABHA at Village Indri (Haryana) on 30<sup>th</sup> October 2021  
to spread awareness and campaign about  
“Complaints under PIDPI”**





**CVO/RITES at RPO/LKO and Mysore site.**



**Essay Writing Competition organized for RITES Employees on 20<sup>th</sup> October 2021.**



# Poster Competition, Vigilance Awareness Week-2020



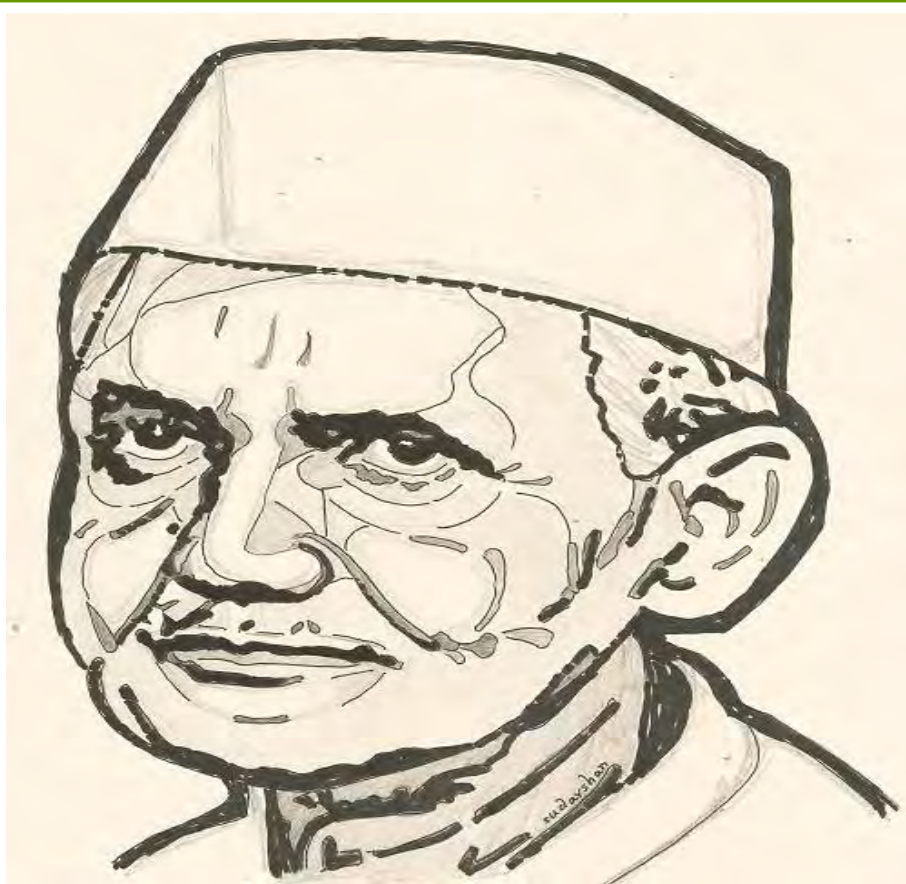
First Prize-Miss Simran, D/o- Shri Abhishek



Second Prize-Miss Rupal,  
D/o-Shri Satish Verma



Third Prize-Miss Kanishka,  
D/o-Shri R.S. Mall



**“Sampling out corruption is a very tough job, but I say so in all seriousness that we would be failing in our duty if we do not tackle this problem seriously and with determination.”**

**— Lal Bahadur Shastri**





**VIGILANCE DEPARTMENT**

**(Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India)**

**Corporate Office : RITES Bhawan No. 1,  
Sector – 29, Gurugram – 122001 (India)**

**Registered office: SCOPE Minar,**

**Laxmi Nagar, Delhi – 110092 (India)**

**Tel- +91-124-2818687**